भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3764

दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता

†3764. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने आत्मनिर्भर लक्ष्य को सरल बनाने के लिए कोई विधान या संशोधन पुर:स्थापित किया है; और
(घ) यदि हां,तो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) महत्वपूर्ण खनिजों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, खान मंत्रालय निम्नलिखित बहुआयामी मार्ग अपना रहा है:

i. महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए संभावित खनन स्थलों की पहचान करने हेतु गवेषण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने चालू वर्ष 2024-25 में देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 196 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

ii. केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 24 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।

iii. मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के माध्यम से खनन गवेषण की विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अब तक, एनएमईटी ने विभिन्न गवेषण एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की 139 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।

iv. गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने 28 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी से वित्त पोषण के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं।

v. खान मंत्रालय के संयुक्त उद्यम काबिल ने लिथियम के गवेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15703 हेक्टेयर क्षेत्र का अधिग्रहण किया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) को दिनांक 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधित किया गया है। संशोधन अधिनियम, 2023 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

i. अनुसूची-I के भाग घ में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची।

ii. अनुसूची-I के भाग ख में 12 परमाणु खनिजों की सूची से छह खनिजों अर्थात लिथियम, टाइटेनियम, बेरिल और बेरिलियम युक्त खनिज, नाईओबियम, टैंटालम और जिरकोनियम युक्त खनिज को हटाना और उन्हें 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची में शामिल करना।

iii. अधिनियम की धारा 11घ जो केंद्र सरकार को अनुसूची-I के भाग घ में विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार देती है।

iv. अधिनियम की अनुसूची-VII में शामिल 29 खनिजों के लिए गवेषण लाइसेंस (ई.एल.) प्रदान करने का प्रावधान।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय को एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 20क के तहत 21 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा गवेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है।

*****